फाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय (एयू)/e6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में अक्टूबर, 2023 माह का मासिक सार ।

अक्टूबर, 2023 माह के लिए न्याय विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. ई-कोर्ट चरण-III पर राज्य विधि सचिवों, राज्य वित्त सचिवों, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल के साथ दिनांक 20.10.2023 को आयोजित सम्मेलन ।

व्यय वित्त समिति, व्यय विभाग, भारत सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के चरण-III को मंजूरी देते हुए राज्य सरकारों को पेश किए जाने वाले भारत सरकार के वित्त पोषण के दो मॉडल (मॉडल 1 और मॉडल 2) की सिफारिश की । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 13.09.2023 को ई-कोर्ट चरण-III के लिए 7210 करोड़ रुपये की मंजूरी देते हुए उपरोक्त सिफारिश को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। मॉडल 1 और मॉडल 2 की विशेषताओं के बारे में राज्यों को अवगत कराना, विशेष रूप से मॉडल-2 के लाभों के बारे में, परियोजना के वित्त पोषण में राज्य की भागीदारी की परिकल्पना करना और भारत सरकार (न्याय विभाग), उच्च न्यायालयों और के बीच हस्ताक्षरित होने वाले त्रिपक्षीय समझौते के विवरण राज्य सरकार, सचिव (न्याय) की अध्यक्षता में ई-कोर्ट चरण-III पर एक सम्मेलन दिनांक 20.10.2023 को आयोजित किया गया था। बैठक में भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, विधि सचिव, वित्त सचिव और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और केंद्रीय परियोजना समन्वयकों ने भाग लिया ।

2. ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण-II:

क. **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) :** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर, दिनांक 01.10.2023 तक, 24.20 करोड़ से अधिक मामलों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है । और कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 23.47 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय देखे जा सकते हैं।

ख. **वर्चुअल कोर्ट:** 3.76 करोड़ से अधिक मामलों को 25 वर्चुअल कोर्टों द्वारा निपटाया गया है और दिनांक 30.09.2023 तक 43 लाख से अधिक मामलों में, 455.12 करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है । चंडीगढ़ में एक नया वर्चुअल कोर्ट शुरू हुआ है, जिससे कुल योग 25 हो गया है ।

ग. **JustIS ऐप:** न्यायिक अधिकारियों के लिए इस मोबाइल ऐप को दिनांक 30.09.2023 तक 19,348 व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किया गया है ।

घ. **ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप:** ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप 30.09.2023 तक कुल 2.03 करोड़ डाउनलोड तक पहुंच गया है।

ङ. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** दिनांक 30.09.2023 तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 2.88 करोड़ (जिला और अधीनस्थ अदालतों द्वारा 2.08 करोड़ मामले और उच्च न्यायालयों द्वारा 79.92 लाख मामले) मामलों की सुनवाई की गई ।

च **ई-सेवा केंद्र:** दिनांक 30.09.2023 तक, 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 869 ई सेवा केंद्र क्रियाशील हो गए हैं।

3. टेली-लॉ: वंचितों तक पहुँच

क. 31 अक्टूबर, 2023 तक, अक्टूबर, 2023 के महीने में 3,60,432 लाभार्थी सहित 56,59,586 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई।

ख. इस महीने के दौरान, वीएलई/पीएलवी, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 24 संघराज्य क्षेत्रों 107 जिलों में आयोजित 149 जागरूकता सत्रों/शिविरों में 2,940 लोगों ने भाग लिया।

ग. वीएलई, राज्य समन्वयक जैसे टेली-लॉ क्षेत्र के पदाधिकारियों के अनुभवों को साझा करने के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम के सेल्फी ड्राइव अभियान के तहत 31 अक्टूबर, 2023 तक 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुल 206 सेल्फी/वीडियो टेली लॉ सोशल मीडिया साइट (फेसबुक और ट्विटर) पर अपलोड किए गए थे।

4. न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम:

इस माह के दौरान 100 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया। न्याय बंधु पोर्टल के तहत कुल 10554 वकील (पुरुष-8838, महिला-1714, ट्रांसजेंडर- 02) पंजीकृत किए गए हैं।

5. कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता (एलएलएलएपी):

क. कानूनी जागरूकता वेबिनार श्रृंखला के हिस्से के रूप में, न्याय विभाग ने 31 अक्टूबर, 2023 को 'बाल यौन शोषण के खिलाफ हितधारकों की संवेदनशीलता' पर 33,318 प्रतिभागियों तक पहुंचते हुए 20वां वेबिनार आयोजित किया । जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मणिपुर के प्रख्यात वक्ताओं ने बाल यौन शोषण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया ।

ख. सामुदायिक अर्थव्यवस्था और विकास सलाहकार केंद्र (सीईसीओईडीईसीओएन), जयपुर, राजस्थान ने 7 पंचायत स्तर के कानूनी जागरूकता सत्र, 9 कानूनी जागरूकता अभियान, 3 ब्लॉक स्तर के स्वयंसेवक प्रशिक्षण और महिला बच्चे और उम्र दराज लोगों के अधिकारों पर एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया और 1,853 लाभार्थियों तक पहुंचा गया ।

ग. जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जेएनआईएमएस), मणिपुर ने बाल यौन शोषण के

खिलाफ हितधारकों के लिए ड्राफ्ट हैंडबुक तैयार की, और इसे दिनांक 31.10.2023 को इनपुट के लिए न्याय विभाग के साथ साझा किया।

घ. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु, कर्नाटक ने द्वितीय कानूनी सहायता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 27 अक्टूबर, 2023 को 48 टीमों के लिए चौथा कानूनी सहायता सम्मेलन आयोजित किया।

6. विशेष अभियान 3.0

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण और मिशन से प्रेरणा लेते हुए, न्याय विभाग ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 शुरू किया । अभियान विभाग में दो चरणों में आयोजित किया गया था - प्रारंभिक चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 था । अभियान का उद्देश्य कार्यालयों और उसके परिसरों की समग्र स्वच्छता में सुधार के साथ-साथ लंबित संदर्भों की पहचान करना और निपटान करना और निपटान की जाने वाली अनावश्यक सामग्रियों की मात्रा का आकलन करना है। 02 अक्टूबर, 2023 को श्रमदान के साथ एक 'जीरो वेस्ट इवेंट' भी आयोजित किया गया था और उसके बाद सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता किट का वितरण किया गया । अभियान के दौरान, प्रारंभिक चरण के दौरान पहचाने गए सभी लंबन सार्वजनिक शिकायतें (139), निराकरण के लिए पहचानी गई भौतिक फ़ाइलें (169), सांसदों के संदर्भ (4), संसदीय आश्वासन (05) को कार्यान्वयन चरण के दौरान समाप्त कर दिया गया । इसके अलावा, 576 वर्ग फुट क्षेत्र को मुक्त कराया गया और लगभग कचरा निपटान से 1.0 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ ।

*****